माननीय न्यायमूर्ति एम. आर. शर्मा और एस. एस. सिद्धू के समक्ष

शेर जंग सिंह और एक अन्य याचिकाकर्ता;
बनाम
वीरिंदर कावर - उत्तरदाता।
1978 का आपराधिक विविध संख्या 1973-एम
20 सितंबर, 1978

भारतीय दंड संहिता (1860 का एक्सएलवी) – धारा 406 - हिंदू: उत्तराधिकार अधिनियम (1956 का 30) - धारा 14 - हिंदू विवाह अधिनियम (1955 का 25) - धारा 27 - दहेज निषेध अधिनियम (1961 का 28) - धारा 2 और 4 - इस्त्रिधन की अवधारणा - क्या अप्रचलित हो गई है - विवाह के समय पत्नी को गहने और अन्य वस्तुओं का उपहार - चाहे वह विशेष रूप से उसके लिए हो - पति या सास-ससुर द्वारा कथित रूप से दुरुपयोग की गई संपत्ति - इस तरह के आरोप - क्या यह आरोप विषय वस्तु बन सकता है। विश्वास का आपराधिक उल्लंघन - धारा 27 - क्या आपराधिक अभियोजन के लिए एक रोक है।
यह अभिनिर्धारित किया गया कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 नामक दो विधियों ने हिंदू कानून के सिद्धांतों को केवल आंशिक रूप से संशोधित किया है और इनमें से किसी भी क़ानून में निहित किसी भी प्रावधान ने स्पष्ट रूप से या किसी भी तरह से इस्त्रिधन की अवधारणा को संशोधित नहीं किया है। एक महिला को अपनी इच्छानुसार किसी भी तरह से अपने इस्त्रिधन का उपयोग करने का पूर्ण अधिकार है और यहां तक कि अगर उसका पति संकट के समय इस संपत्ति को ले सकता है, तो यह अधिकार उसके लिए व्यक्तिगत है। दहेज की पुरानी अवधारणा जो नवविवाहित पत्नी को दिए गए उपहारों को अपने दायरे में लेती थी, जो उसके इस्त्रिधन का हिस्सा बनने वाली थी, दहेज निषेध अधिनियम, 1961 के प्रावधानों से भी प्रभावित नहीं हुई है।

(पैरा 8, 9 और 12)

यह अभिनिर्धारित किया गया कि एक पत्नी को उसकी शादी के समय प्रस्तुत किए गए कुछ लेख पति-पत्नी दोनों के उपयोग के लिए हो सकते हैं, लेकिन समान प्रकृति के गहने और चीजें निश्चित रूप से उसके और उसके लिए हैं। जब वह शिकायत में यह आरोप लगाती है कि या तो उसके पति या उसके सास-ससुर ने उसके इस्त्रिधन के हिस्से के रूप में गहने को अपने स्वयं के उपयोग में परिवर्तित कर दिया था, जिसे उसने उन्हें सौंपा था, तो अदालत को ऐसे आरोपों को कानूनी रूप देना होगा और यह मानना होगा कि ऐसे गहने आपराधिक विश्वासघात का विषय बना दिए गए थे – यह स्थापित कानून है कि आपराधिक शिकायत में भी शिकायतकर्ता लगाए गए आरोपों के कानूनी प्रभाव की दलील देने के लिए बाध्य नहीं है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि शिकायत का गठन करने वाले तथ्यों का विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए ताकि अदालत ऐसे आरोप लगाए जाने पर कानून के उचित प्रावधानों के तहत आरोपी को दंडित करने के अपने कर्तव्य का पालन करने में सक्षम हो सके।

(पैरा 13)

यह अभिनिर्धारित किया गया कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 27 वैवाहिक विवाद पर फैसला करते समय अदालत को संपत्ति के संबंध में एक डिक्री पारित करने का अधिकार देती है जो संयुक्त रूप से पति और पत्नी दोनों से संबंधित हो सकती है। यह धारा अधिक से अधिक पीड़ित पत्नी को एक नागरिक उपचार प्रदान करती है और किसी भी तरह से आपराधिक शिकायत दर्ज करने के उसके अधिकार को नहीं छीनती है यदि उससे संबंधित संपत्ति उसके पति या सास-ससुर द्वारा आपराधिक रूप से दुरुपयोग की जाती है।
सुरिंदर मोहन और अन्य बनाम श्रीमती किरण सैनी, (1977) चंडीगढ़ लॉ रिपोर्टर 212 ख़ारिज।

सीआरपीसी की धारा 482 के तहत आवेदन में अनुरोध किया गया है कि याचिकाकर्ताओं को आरोपी के रूप में तलब करने वाले याचिका पत्र पी/2 और अनुलग्नक पी/3 को अदालत की प्रक्रिया और शिकायत की कार्यवाही का दुरुपयोग मानते हुए रद्द कर दिया जाए।

याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील के एस थापर, आर एस पाल्टा, एस एस चोपड़ा और दीपक थापर, एडवोकेट।
हरभगवान सिंह, सीनियर एडवोकेट और जे. एस. चहल प्रतिवादी की ओर से एडवोकेट।

निर्णय

माननीय न्यायमूर्ति एम. आर. शर्मा- (मौखिक)

1) याचिकाकर्ता नंबर 1 और 2 प्रतिवादी के क्रमशः ससुर और सास हैं। बाद में उन्होंने चंडीगढ़ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के तहत शिकायत दर्ज की। उस शिकायत में यह कहा गया था कि प्रतिवादी का विवाह याचिकाकर्ताओं के बेटे इकबाल जंग सिंह के साथ 27 मार्च, 1977 को चंडीगढ़ में आनंद कारज समारोह द्वारा किया गया था, जो पार्टियों के समुदाय में प्रचलित विवाह का प्रथागत रूप है। अपनी शादी के समय, प्रतिवादी को अपने माता-पिता, रिश्तेदारों, अपने पति और याचिकाकर्ताओं से गहने, कपड़े, फर्नीचर और अन्य घरेलू वस्तुओं के पर्याप्त उपहार प्राप्त हुए। संपत्ति की ये वस्तुएं, जिन पर उनका पूर्ण नियंत्रण था, उनके अनुसार, उनका धर्म बन गया। याचिकाकर्ताओं की कर्तव्यपरायण बहू के रूप में, उन्होंने उन पर पूरा विश्वास जताया और यह सारी संपत्ति उन्हें सौंप दी। उन्होंने इस आधार पर गहनों के उपयोग की अनुमति नहीं दी (जो शिकायत के अनुबंध 'ए' में उल्लिखित वस्तुओं के अनुसार एक लाख रुपये से अधिक मूल्य के थे) कि "मूल्यवान गहने पहनने के लिए समय सुरक्षित नहीं था"।
2) शिकायत में कहा गया है कि जून, 1977 में प्रतिवादी के पति इकबाल जंग सिंह एक व्यावसायिक यात्रा के बहाने अमेरिका चले गए। देश छोड़ने से पहले, उन्होंने प्रतिवादी से कहा कि गहने आदि उनके माता-पिता, यानी याचिकाकर्ताओं की सुरक्षित कस्टडी में रहने चाहिए। प्रतिवादी के पास उसके बयान पर संदेह करने का कोई आधार नहीं था और उसने उसी पर कार्रवाई की, हालांकि बाद में यह पता चला कि यह उसके माता-पिता की मिलीभगत से प्रतिवादी को छोड़ने की योजना थी। यू.एस.ए. के लिए उसके पति के प्रस्थान के बाद उसके प्रति याचिकाकर्ताओं का रवैया पूरी तरह से बदल गया और उन्होंने उसे ताना मारना शुरू कर दिया। बसंत पंचमी के दिन, यानी 12 फरवरी, 1978 को, प्रतिवादी ने बसंत मनाने के लिए उन्हें पहनने के लिए गहनों का एक सेट मांगा, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने उसे कोई भी आभूषण देने से इनकार कर दिया और उसे दो टूक कहा कि उसे उन गहने और दहेज की वस्तुओं को उपयोग के लिए रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उसे आगे ताना मारा गया और अपने माता-पिता से एक लाख रुपये लाने के लिए कहा गया। याचिकाकर्ताओं का व्यवहार न केवल अशिष्ट था बल्कि स्थिति के कोमल दलों के लिए भी अनुपयुक्त था। इसमें कहा गया है, 'आरोपी ने शिकायतकर्ता को गाली दी और थप्पड़ मारा, हीरे की अंगूठी, कलाई घड़ी, सोने का हार और सोने की कान की अंगूठियां जबरन ले लीं और शिकायतकर्ता को केवल उन्हीं कपड़ों में घर छोड़ने के लिए मजबूर किया जो शिकायतकर्ता ने पहने हुए थे और कहा कि वह कभी वापस न लौटे और शिकायतकर्ता को गहने और अन्य सामान नहीं मिलेगा.'
3) कुछ अन्य तथ्यों का उल्लेख करने के बाद, शिकायत में कहा गया है कि "आरोपियों ने शिकायतकर्ता के स्वामित्व वाले गहनों और अन्य वस्तुओं के विश्वास का आपराधिक उल्लंघन करके आईपीसी की धारा 406 के तहत अपराध किया है, जो उसके इश्रिधन हैं जो आरोपी को

सुरक्षित हिरासत के लिए सौंपे गए थे और जिसे आरोपियों ने बेईमानी से दुरुपयोग किया है। कौन सा अपराध संज्ञेय है और इस न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य है। अंत में, यह प्रार्थना की गई कि उन पर मुकदमा चलाया जाए और कानून के अनुसार उचित रूप से दंडित किया जाए और अनुबंध ए और बी में उल्लिखित लेखों को उन्हें वापस करने का आदेश दिया जाए।

4) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा 21 मार्च, 1978 को पारित आदेश से पता चलता है कि प्रतिवादी ने खुद को गवाह-बॉक्स में प्रवेश करने के अलावा अपनी बहन दलजिंदर कौर पीडब्ल्यू 2 और गुरिंदर सिंह पीडब्ल्यू 3 को शिकायत में उल्लिखित संस्करण के समर्थन में पेश किया। प्रतिवादी द्वारा दिए गए बयान की विस्तृत समीक्षा करने के बाद विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने संतुष्ट महसूस किया कि याचिकाकर्ताओं ने प्रथम दृष्टया आईपीसी की धारा 406 के तहत अपराध किया है। तदनुसार उन्हें आरोपी व्यक्तियों के रूप में तलब करने का आदेश दिया गया था।

5) दोनों याचिकाकर्ताओं ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत तत्काल याचिका दायर की है, जिसमें अनुरोध किया गया है कि प्रतिवादी द्वारा दायर शिकायत और 21 मार्च, 1978 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया जाए, जिसमें उन्हें आरोपी व्यक्तियों के रूप में तलब किया गया था। इसमें उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता नंबर 1 सिद्धोवाल का रईस है, जिसने लाहौर के ऐचेसन चीफ कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज, लाहौर में अपनी शिक्षा प्राप्त की है। वह भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य के रूप में सेवानिवृत्त हुए। यह स्वीकार किया गया कि याचिकाकर्ताओं के इकलौते बेटे श्री इकबाल जंग सिंह का विवाह 27 मार्च, 1977 को प्रतिवादी से हुआ था, लेकिन समाज को एक नेतृत्व देने के लिए और उनकी सामाजिक स्थिति के कारण उन्होंने विवाह या अपने इकलौते बेटे के समय कोई भी उपहार या दहेज स्वीकार करने से इनकार कर दिया। याचिका में कहा गया है कि शादी के तुरंत बाद यह पता चला कि प्रतिवादी को अपने पति में कोई दिलचस्पी नहीं हो सकती है। बताया जाता है कि उसकी बड़ी बहन की शादी सरदार जसबीर सिंह पुत्र अजीत सिंह निवासी गांव बुराज, जिला अमृतसर के साथ हुई थी। उक्त सरदार अजीत सिंह कुछ अन्य लोगों के साथ तिहरे हत्याकांड में शामिल था। यह मामला इन आरोपों से उत्पन्न हुआ कि तीन मृत व्यक्तियों को क्रिस्टल चौक, अमृतसर से अपहरण कर लिया गया था, सीमा सुरक्षा बल के सदस्यों की मिलीभगत से यातना दी गई थी और उनकी हत्या कर दी गई थी, लेकिन मामला भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बरी कर दिया गया था। यह दावा किया गया है कि प्रतिवादी 7 मई, 1977 को छह घंटे तक अपने पति से बचती रही और कहीं भी नहीं मिली जहां उसे होना चाहिए था। उनकी ओर से इस चूक के लिए उनके पास कोई स्पष्टीकरण नहीं था। इसके अलावा लॉकर नंबर 26 को इकबाल जंग सिंह और प्रतिवादी के संयुक्त नाम पर आंध्रा बैंक में किराए पर लिया गया था, जिसे संयुक्त रूप से या अलग-अलग संचालित किया जा सकता था और 28 अप्रैल, 1977 को प्रतिवादी ने अकेले लॉकर का संचालन किया। सात मई, 1977 को याचिकाकर्ताओं के घर से जाने के बाद याचिकाकर्ताओं के बेटे इकबाल जंग सिंह ने नौ मई, 1977 को लॉकर का संचालन किया और पाया कि उसमें कुछ भी नहीं है। याचिका में दावा किया गया है कि 12 फरवरी, 1978 तक याचिकाकर्ताओं के घर में रहने की उनकी शिकायत गलत थी और याचिकाकर्ताओं ने कभी भी उनके माता-पिता से किसी राशि की मांग नहीं की। 7 मई, 1977 के बाद, याचिकाकर्ताओं को संदिग्ध टेलीफोन कॉल आने लगे, जिसने उन्हें अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा और अपने बेटे की सुरक्षा के बारे में बहुत चिंतित कर दिया। याचिकाकर्ता इकबाल जंग सिंह का बेटा 14 जून, 1977 को और जून की रात को हवाई मार्ग से अमेरिका के लिए रवाना हुआ। 22 दिसंबर, 1977 को ड्राइंग-रूम की खिड़की पर तीन रिवॉल्वर शॉट दागे गए, जहां याचिकाकर्ता नंबर 1 बैठा करता था। इस मामले को किसी के खिलाफ कोई संदेह व्यक्त किए बिना पुलिस को सूचित किया गया था। शिकायत की क्षमता के बारे में कानूनी आपत्तियां याचिका के पैराग्राफ नंबर 16 से 20 में उठाई गई हैं, जो निम्नानुसार है:-

"16. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम और हिंदू विवाह अधिनियम के पारित होने के बाद प्रतिवादी का यह दावा कि विवाह के समय उसे उपहार में दी गई संपत्ति उसकी इश्रिधन है, कानूनी रूप से मान्य नहीं है और ऐसी संपत्ति अब हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 27 द्वारा शासित है, जो इसे पार्टियों की संयुक्त संपत्ति बनाती है।

17. यह कि प्रतिवादी ने अपनी मर्जी से वैवाहिक घर छोड़ दिया है और यहां तक कि झूठे आरोप कि उसे घर से बाहर कर दिया गया था, इसका मतलब यह नहीं है कि शिकायत के अनुसार, जिस संपत्ति को वैवाहिक घर में लाया गया था, उसका दुरुपयोग किया गया है। हिंदू विवाह अधिनियम में प्रदान किए गए उपाय का लाभ उठाना होगा।

18. यहां तक कि हिंदू कानून के अस्तित्व का मतलब यह नहीं है कि महिला में निपटान की असीमित शक्ति है। इस सिद्धांत ने ऐसी संपत्ति की विरासत को नियंत्रित किया और महिला को वंश का नया भंडार बनाया और बेटे पर बेटियों को प्राथमिकता दी।

19. कि वर्तमान कानून के तहत इस्त्रीधन के आधार पर कोई दावा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसे अब पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है और कानून के खिलाफ इसका लाभ नहीं उठाया जा सकता है जो इसे पार्टियों की संयुक्त संपत्ति बनाता है (19'77 चंडीगढ़ लॉ रिपोर्टर 212)।

20. चूंकि संपत्ति उपहार में दी गई थी और पार्टियों का संयुक्त था, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि इसका दुरुपयोग किया गया है या एक अलग और बेईमान उपयोगकर्ता को परिवर्तित किया गया है, क्योंकि वह पार्टियों के पास संयुक्त रूप से इस संपत्ति का स्वामित्व है और संपत्ति को किसी भी उपयोग में परिवर्तित नहीं किया गया है, जो आरोपों की सच्चाई स्वीकार होने पर भी निहित हो सकता है।"

6) जब यह मामला सुनवाई के दौरान सामने आया, तो याचिकाकर्ताओं के वकील थापर ने सुरिंदर मोहन और अन्य बनाम सिंध मामले में इस न्यायालय की एकल पीठ के फैसले को मेरे ध्यान में लाया। किरण सैनी, (1977) चंडीगढ़ लॉ रिपोर्टर 212 | उस मामले में एक पत्नी द्वारा अपने पति के खिलाफ दायर इसी तरह की शिकायत को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि दहेज अधिनियम की धारा 4 के तहत शिकायत उक्त अधिनियम की धारा 7 के तहत निर्धारित एक वर्ष की अवधि के बाद संज्ञेय नहीं थी और धारा 406 के तहत अपराध नहीं बनता था क्योंकि शिकायत में उन शर्तों का खुलासा नहीं किया गया था जिनके तहत दहेज का गठन करने वाली वस्तुएं दी गई थीं। उस मामले में पति या पत्नी के विवाह के समय लड़की का माता-पिता। प्रथम दृष्टया मेरा विचार था कि उस लेख की कुछ टिप्पणियों से इस देश में अनपढ़ और असहाय पत्नियों के विरुद्ध कठिनाई उत्पन्न होने की संभावना है। नतीजतन, मैंने पुनरीक्षण याचिका को एक खंडपीठ द्वारा सुनवाई और निर्णय के लिए स्वीकार कर लिया। इस तरह वर्तमान मामला हमारे सामने बहस के लिए आया है।

7) याचिकाकर्ताओं के वकील श्री थापर ने जोरदार तर्क दिया है कि हिंदू कानून के बाद के संहिताकरण के कारण इश्रिधन की अवधारणा गायब हो गई है और एक पति या उसके माता-पिता को विश्वासघात करने का दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, भले ही वे पत्नी को उसकी शादी के समय दिए गए गहने और अन्य वस्तुओं को बनाए रखें। अपने तर्क के समर्थन में, विद्वान वकील ने हमें हिंदू कानून पर विभिन्न पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से ले जाया है। हिंदू कानून और उपयोग पर मेन के ग्रंथ में, पृष्ठ 728 पर ग्यारहवां संस्करण, निम्नलिखित अंश दिखाई देता है:-

"विरामित्रोदय के अनुसार, विवाह के समय वर और वधू को एक ही आसन पर बैठकर जो कुछ भी दिया जाता है, उसे व्युत्पत्ति के माध्यम से यौतक कहा जाता है, 'जो 'युताऊ' (या दोनों एकजुट) से संबंधित है, वह 'योतक' है। अयुतक वह है जो यौतक नहीं है। "मुथुकरुप्पा वी। सेल्थाम्मल, यह कहा गया था "यौतक वह है जो विवाह की अग्नि में दिया जाता है, इसमें विवाह समारोहों के दौरान किए गए सभी उपहार शामिल होते हैं। अयाउतक शादी से पहले या बाद में दिया गया उपहार है। सौदायिका में यौतक और अयुतक दोनों शामिल हैं जो अजनबियों से प्राप्त नहीं होते हैं। इसे स्नेही लोगों से उपहार के रूप में परिभाषित किया गया है।"

"उसका पति न तो उसके साथ उसके व्यवहार में उसे नियंत्रित कर सकता है, न ही खुद इसका उपयोग कर सकता है। लेकिन चरम के मामले में वह इसे ले सकता है संकट, जैसे कि अकाल में, या किसी अपरिहार्य कर्तव्य के लिए, या बीमारी के दौरान, या जब एक लेनदार उसे जेल में रखता है। फिर भी वह कम से कम एक नैतिक दायित्व के तहत प्रतीत होगा कि वह संपत्ति के मूल्य को बहाल करे जब ऐसा करने के लिए एबीएम हो। उन्होंने जो कुछ भी बिना जरूरत के लिया है, वह ब्याज के साथ चुकाने के लिए बाध्य हैं। (पृष्ठ 736-737)"

8) इन परिच्छेदों में से 1 में कहा गया है कि विवाह के समय उत्तरदाताओं को दिए गए गहने और गुंबद पति-पत्नी के लिए दान का उपयोग करने के लिए थे, और नुसबैंड कॉइड वास्तव में टिन की संपत्ति का उपयोग करता है, क्योंकि अत्यधिक संकट की स्थिति में यह संपत्ति ब्याज के साथ वापस करने का नैतिक दायित्व है। ब्याज का भुगतान करने का दायित्व, विद्वान वकील प्रस्तुत करता है, यह दर्शाता है कि ऐसी संपत्ति कभी भी विश्वास के आपराधिक उल्लंघन का विषय नहीं बन सकती है। वकील ने हमें हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 27 का हवाला दिया, जो अदालत को एक डिक्री पारित करने का अधिकार देता है, जिसमें नुसबैंड को निर्देश दिया जाता है कि वह पत्नी को उसके गहने और अन्य सामान वापस करे। उन्होंने तर्क दिया कि प्रतिवादी इस धारा के तहत एक याचिका दायर कर सकता है और गहने आदि की वापसी के लिए डिक्री का दावा कर सकता है। इस बिंदु पर उठाया गया अंतिम तर्क यह था कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 के तहत एक महिला अपनी संपत्ति की पूर्ण मालिक बन गई थी, जिसका अर्थ था कि इश्रिधन की अवधारणा पूरी तरह से अप्रचलित हो गई थी। हमने श्री थापर द्वारा दिए गए इन बेतुके तर्कों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है। हिंदू विवाह अधिनियम और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम नामक दो विधियों ने हिंदू कानून के सिद्धांतों को केवल आंशिक रूप से संशोधित किया है, और इनमें से किसी भी क़ानून में निहित किसी भी प्रावधान ने स्पष्ट रूप से या किसी भी तरह से इस्त्रिधन की अवधारणा को संशोधित नहीं किया है। एन. आर. राघवाचरियार ने अपने हिंदू कानून (सिद्धांत और मिसालें) में लिखा है। पृष्ठ 533 पर पांचवां संस्करण निम्नानुसार देखा गया है:-

"विवाह के दौरान शक्तियाँ।—सौदयाका का अर्थ है स्नेही उपहार का उपहार, जिसमें विवाह के समय प्राप्त यौतक या उपहार के साथ-साथ इसके नकारात्मक अयुतक भी शामिल हैं। ऐसी संपत्ति के संबंध में, चाहे उपहार या वसीयत द्वारा दी गई हो, वह पूर्ण मालिक है और किसी भी तरह से इससे निपट सकती है। वह खर्च कर सकता है, बेच सकता है या दे सकता है! यह अपने पति के संदर्भ के बिना उपहार या इच्छा से अपनी खुशी से दूर हो जाता है और इसके द्वारा अर्जित संपत्ति समान रूप से ऐसे अधिकारों के अधीन है। आमतौर पर पति के पास इसमें अधिकार या रुचि का कोई तरीका नहीं होता है। लेकिन अत्यधिक संकट के समय में, जैसे कि अकाल, बीमारी या कारावास, या। अपरिहार्य कर्तव्य के प्रदर्शन के लिए, पति इसे अपने व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए ले सकता है और उपयोग कर सकता है, हालांकि तब

भी वह ऐसा करने में सक्षम होने पर इसे या इसके मूल्य को बहाल करने के लिए नैतिक रूप से बाध्य है। लेकिन यह अधिकार पूरी तरह से उसके लिए व्यक्तिगत है और पति के खिलाफ डिक्री के धारक द्वारा इसका लाभ नहीं उठाया जा सकता है और यदि नुसबैंड अपने ऋणों के परिसमापन के लिए संपत्ति का उपयोग किए बिना मर जाता है, तो उसके लेनदार अपने पति के स्थान पर इसके खिलाफ आगे बढ़ने का दावा नहीं कर सकते हैं। लेकिन गैर-सौदायिका संपत्ति के मामले में स्थिति अलग है। कात्यायन के अनुसार, "वह धन जो यांत्रिक कलाओं द्वारा अर्जित किया जाता है, या जो किसी अन्य (लेकिन दयालु) से स्नेह के माध्यम से प्राप्त होता है, वह हमेशा पति के नियंत्रण में होता है" और दयाभागा के अनुसार उन्हें संकट के अभाव में भी इसे लेने का अधिकार है। इसलिए गैर-सौदा यिका संपत्ति के मामले में, पति की सहमति उसके निपटान की शक्ति के लिए एक शर्त है और वह किसी भी बाध्यकारी आवश्यकता के अभाव में भी अपने स्वयं के उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग करने का हकदार है। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद, उसके स्वभाव की शक्ति निरंकुश हो जाती है। यहां तक कि पति के जीवनकाल के दौरान भी पत्नी उसकी मालिक नहीं रहती है, हालांकि पति के पास उपरोक्त अधिकार है। इसलिए यदि पति के जीवनकाल के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है, तो संपत्ति उसके उत्तराधिकारियों द्वारा ली जाती है, न कि उसके पति के उत्तराधिकारियों द्वारा। (पृष्ठ 533-534)।"

9) उपरोक्त अंश से पता चलता है कि एक फर्नी को अपने इस्तरिधन का उपयोग करने का पूर्ण अधिकार है 'किसी भी तरह से वह पसंद करती है और भले ही उसका पति संकट के समय इस संपत्ति को ले सकता है, यह अधिकार उसके लिए व्यक्तिगत है। तत्काल शिकायत में लगाए गए आरोप यह नहीं हैं कि प्रतिवादी के पति ने उसके गहने और गहने आदि उसके रास्ते से बाहर रख दिए हैं। इसमें जो आरोप लगाया गया है वह यह है कि याचिकाकर्ता जो प्रतिवादी के सास-ससुर हैं, ने प्रतिवादी को उसकी शादी के समय प्रस्तुत किए गए गहने और कपड़े आदि को अपने स्वयं के उपयोग में बदल दिया है।
10) हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 27 वैवाहिक विवाद पर फैसला करते समय अदालत को संपत्ति के संबंध में एक डिक्री पारित करने का अधिकार देती है जो संयुक्त रूप से पति और पत्नी दोनों से संबंधित हो सकती है। यह धारा किसी पीड़ित पत्नी को एक नागरिक उपचार प्रदान करती है और किसी भी तरह से आपराधिक शिकायत दर्ज करने के उसके अधिकार को नहीं छीनती है यदि उससे संबंधित संपत्ति उसके पति द्वारा आपराधिक रूप से दुरुपयोग की जाती है।
11) अब हम इस तर्क की जांच कर सकते हैं कि प्रतिवादी को उसके विवाह के समय प्रस्तुत लेख 'दहेज' या उसके धर्म का गठन नहीं करते थे। इस संबंध में, हम देख सकते हैं कि दहेज निषेध अधिनियम, 1961, एक विशेष क़ानून है जिसे पतियों को शादी के लिए भारी रकम निकालने से रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है। 'दहेज' शब्द को इस अधिनियम की धारा 2 में निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:-

"दहेज की परिभाषा- इस अधिनियम में, 'दहेज' का अर्थ है कोई भी संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दी गई या देने के लिए सहमत है-

a) विवाह के लिए दूसरे पक्ष से विवाह के लिए एक पक्ष द्वारा;
b) नहीं तो विवाह के किसी भी पक्ष के माता-पिता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, विवाह के पक्ष या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा;

विवाह से पहले या बाद में- उक्त पक्षों के विवाह के लिए विचार के रूप में, लेकिन उन व्यक्तियों के मामले में डोवर या महर को शामिल नहीं करता है जिन पर मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) लागू होता है।

स्पष्टीकरण। – संदेह को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि विवाह के समय नकद, गहने, कपड़े या अन्य वस्तुओं के रूप में विवाह के किसी भी पक्ष को दिया गया कोई भी उपहार इस धारा के अर्थ के भीतर दहेज नहीं माना जाएगा, जब तक कि उन्हें उक्त पक्षों के विवाह के लिए विचार नहीं किया जाता है।

स्पष्टीकरण ॥.- 'मूल्यवान सुरक्षा' शब्द का वही अर्थ है जो भारतीय दंड संहिता की धारा 80 में है।"

12) पहला स्पष्टीकरण, इस खंड के तहत पूरी स्थिति को प्रकट करता है। यह किसी को भी अपने विवाह के समय नवविवाहित पति-पत्नी को स्वेच्छा से उपहार देने से मना नहीं करता है। इसमें निहित एकमात्र अवरोध यह है कि इस तरह के उपहार ोें को विवाह के लिए विचार के रूप में नहीं बनाया जाएगा! दलों। शर्त यह है कि किसी भी पक्ष को सौदेबाजी करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए कि दो व्यक्तियों के बीच विवाह की स्थिति में एक या दूसरे पक्ष को एक निर्दिष्ट राशि के साथ भाग लेना होगा। स्पष्टीकरण आगे यह स्पष्ट करता है कि 'दहेज' शब्द को केवल इस अधिनियम के उद्देश्य के लिए एक विशेष अर्थ दिया गया है। दूसरे शब्दों में, यदि कोई सौदा किया जाता है या दो व्यक्तियों के विवाह के लिए विचार के रूप में कुछ पैसे वसूले जाते हैं, तो व्यक्ति; दहेज की मांग करने पर इस अधिनियम की धारा 4 के तहत सजा दी जाएगी। दहेज की पुरानी अवधारणा जो नवविवाहित पत्नी को दिए गए उपहारों को अपने दायरे में लेती थी, जो उसके इश्रिधन का हिस्सा बनने वाली थी, दहेज निषेध अधिनियम के प्रावधानों से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुई है।

13) यह हो सकता है कि उसके सामने प्रस्तुत किए गए कुछ लेख दोनों पति-पत्नी के उपयोग के लिए हैं, लेकिन समान प्रकृति के गहने और चीजें निश्चित रूप से उसके और उसके लिए हैं। जब वह शिकायत में यह आरोप लगाती है कि या तो उसके पति या उसके सास-ससुर ने उसके इश्रिधन के हिस्से के रूप में गहने को अपने स्वयं के यूइस में परिवर्तित कर दिया था, जिसे उसने उन्हें सौंपा था, तो अदालत को ऐसे आरोपों को कानूनी रूप देना होगा और यह मानना होगा कि ऐसे गहने आपराधिक विश्वासघात का विषय बन गए थे। यह स्थापित कानून है कि आपराधिक शिकायत में भी शिकायतकर्ता लगाए गए आरोपों के कानूनी प्रभाव की दलील देने के लिए बाध्य नहीं है। इसके लिए आवश्यक है कि शिकायत का गठन करने वाले तथ्यों का विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए ताकि न्यायालय ऐसे आरोप लगाए जाने पर कानून के उचित प्रावधान के तहत आरोपी को दंडित करने के अपने कर्तव्य का पालन करने में सक्षम हो सके। ; इसके अलावा, इस तरह के मामले में पीड़ित पत्नी को यह साबित करने का अवसर दिए बिना शिकायत को रद्द नहीं किया जा सकता है कि गहने उसकी शादी के समय केवल उसके उपयोग के लिए दिए गए थे। सुरिंदर मोहन और अन्य बनाम श्रीमती किरण सैनी (सुप्रा) में इसके विपरीत की गई किसी भी टिप्पणी को अच्छा कानून नहीं माना जा सकता है।

14) अब, शिकायत और उसके साथ संलग्न अनुलग्नकों को पढ़ने से स्पष्ट रूप से संपत्ति की कुछ वस्तुओं का पता चलता है जो पूरी तरह से प्रतिवादी के उपयोग के लिए हैं। इस स्थिति में इस स्तर पर शिकायत को रद्द करना हमारी ओर से उचित नहीं होगा।

15) श्री थापर ने तब प्रस्तुत किया कि शिकायत को पढ़ने से कोई अपराध नहीं बनता है और आरोप ऐसे थे। तुच्छ है कि शिकायत संभवतः याचिकाकर्ताओं की दोषसिद्धि का परिणाम नहीं हो सकती है। हम विद्वान वकील द्वारा की गई इस दलील से सहमत नहीं हैं। शिकायत में एक निश्चित आरोप है कि प्रतिवादी को उसकी शादी के समय दिए गए गहने उसके द्वारा याचिकाकर्ताओं को सौंपे गए थे, जिनमें से कुछ ने मांग करने पर भाग लेने से इनकार कर दिया था। वह इस आरोप को साबित कर पाएंगी या नहीं, यह पूरी तरह से 'अलग मामला है और इस स्तर पर हमारे लिए यह मान लेना संभव नहीं है कि वह इन आरोपों के समर्थन में कोई सबूत पेश नहीं कर पाएंगी। इसमें

कोई संदेह नहीं है कि एक आपराधिक मामले में आरोप साबित करने का बोझ शिकायतकर्ता पर होता है और एक आरोपी व्यक्ति संदेह का लाभ पाने का हकदार होता है, लेकिन ये सिद्धांत काफी अच्छी तरह से ज्ञात हैं और हमारे मन में कोई संदेह नहीं है कि विद्वान ट्रायल मजिस्ट्रेट शिकायत की कोशिश करते समय उन्हें ध्यान में रखेंगे। इन परिस्थितियों में, हम याचिका में कोई बल नहीं पाते हैं और इसे खारिज करते हैं।

16) मामले से अलग होने से पहले, हम देख सकते हैं कि पार्टियों की स्थिति को देखते हुए हमने उनके बीच समझौता करने की पूरी कोशिश की लेकिन असफल रहे। फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य की किसी तारीख पर यह बदसूरत मुकदमा समाप्त हो जाएगा और दोनों पति-पत्नी एक बार फिर एक साथ रहने का फैसला करेंगे। उस आशा से प्रेरित होकर, हम निर्देश देते हैं कि विद्वान ट्रायल मजिस्ट्रेट याचिकाकर्ताओं को अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट देगा, जब तक कि यह हो; आवश्यक महसूस होता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

हिमांशु जांगड़ा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी